RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. सोमवार, 11 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 165 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु.

संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किया कैंसिल

नई दिल्ली – चुनाव आयोग ने 334 रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन दलों ने 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा था और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं मिला। आयोग का यह कदम बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक पारदर्शिता और सिस्टम की सफाई की दिशा में अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी कि RUPP का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन पार्टियों ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिल सका। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आयोग का इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। RUPP यानी Registered Unrecognised Political Parties, वे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है। ये दल भारत में प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें टैक्स छूट जैसे कुछ विशेष लाभ मिलते हैं। देश में कुल 2,854 RUPP थे, जिनमें से चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब 2,520 बचे हैं।चुनाव आयोग ने इन 334 दलों को इसलिए हटाया क्योंकि इन्होंने 2019 के बाद से न तो लोकसभा, न राज्य विधानसभा और न ही उप-चुनाव में हिस्सा लिया। इन दलों के दफ्तरों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं पाया गया। आयोग ने जब जांच की, तो ये दल कागजों तक ही सीमित थे। कुछ RUPP पहले आयकर नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए थे। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने पहले राजनीतिक दलों को 'मान्यता रद्द' करने से रोका था, क्योंकि कानून में इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन आयोग ने 'डीलिस्टिंग' का रास्ता निकाला। डीलिस्टिंग का मतलब है कि इन दलों को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत, कोई भी पंजीकृत दल अगर लगातार 6 साल तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। हालांकि, ये दल बिना नई मान्यता प्रक्रिया के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश में अब 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2,520 RUPP बचे हैं। आयोग ने 2001 से अब तक 3-4 बार ऐसी सफाई की है। इस बार जून 2025 में 345 दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, जिनमें से 334 का पंजीकरण रद्द किया गया। डीलिस्ट किए गए दल अब चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे। यह कदम बिहार चुनाव से पहले इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी दलों पर लगाम लगेगी।

पुलिस थानों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों को न्यूनतम वेतन दें – योगेश कदम

मुंबई – गृह राज्यमंत्री (शहरी) योगेश कदम ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार राज्य के पुलिस थानों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों के लिए 27 जनवरी 2017 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम वेतन के संबंध में कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, "राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 1800 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए। राज्य के सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, गृह विभाग के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को भी भुगतान किया जाना चाहिए।" विभाग में स्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए लैड-पेज समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों को 2017 के सरकारी निर्णय के अनुसार वेतन देते समय, पिछले बकाया भुगतान के संबंध में चर्चा की गई है और किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा निर्देश राज्य मंत्री श्री कदम ने दिया। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अभिषेक त्रिमुखे, उप सचिव रवींद्र पाटिल, उदय भट, जीवन सुरुडे और महाराष्ट्र राज्य श्रमिक संघ के अन्य लोग उपस्थित थे।

माफिया के खिलाफ राजस्व मंत्री के स्पष्ट निर्देश

अवैध रेत खनन और परिवहन में शामिल लोगों पर एमपीडीए लगाए

बुलढाणा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जिले में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शनिवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ एमपीडीए यानी महाराष्ट्र खतरनाक व्यक्ति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। राजस्व मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुले ने कल जिले का दौरा कर राजस्व, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण, भूमि अभिलेख विभाग की समीक्षा की। इसी क्रम में उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय के नियोजन समिति हॉल में राजस्व और अन्य विभागों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री बावनकुले ने निर्देश दिए। इस बैठक में श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर, विधायक श्वेता महाले, विधायक संजय गायकवाड़, विधायक मनोज कायंदे, जिला कलेक्टर डॉ. किरण पाटिल, पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, उप-वन संरक्षक सरोज गवस, सभी उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित थे।

इस बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिले में अवैध गौण खनिज खनन और परिवहन में शामिल लोगों और इसमें शामिल राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि अवैध गौण खनिज खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते समय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई न करें और रेत माफिया को खुला न छोड़ें। राजस्व मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि अब से जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इसके अलावा, जिले में रेत के भंडारों और रेत घाटों का फिर से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदारों को एमआर एसएसी प्रणाली का निरीक्षण और उपयोग करना चाहिए। साथ ही, नई रेत नीति के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृत्रिम रेत नीति के तहत रेत की गुणवत्ता उच्च हो। गरीब और आम लोगों को उनके घरों के लिए रेत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अवैध रेत परिवहनकर्ताओं से लंबित जुर्माना वसूला जाना चाहिए। बंजर भूमि पर घरों के मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए, इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। सरकारी जमीनों को अवैध रूप से हड़पने वाले साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पनंद और शिवार सड़कों को साफ किया जाना चाहिए। तदनुसार, गांववार नक्शे तैयार किए जाने चाहिए और दृश्य क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए। नागरिकों की शिकायतों और मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाना चाहिए गरीब, दरिद्र और गरीब की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकारी नीति के अनुसार, दिसंबर माह तक ऑक्युपियर क्लास 2 की जमीनों को ऑक्युपियर क्लास 1 में परिवर्तित किया जाए। किसानों से इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील की जाए।

सही से केस नहीं लड़ा तो घोंट दिया वकील का गला

झांसी – 62 वर्षीय रिटायर्ड वकील भानु प्रकाश सरवरिया की उनके पड़ोसी सचिन वर्मा ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को लगता था कि वकील ने एक पुराने केस में ठीक से उसकी पैरवी नहीं की थी। पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 62 साल के रिटायर्ड वकील भानु प्रकाश सरवरिया की उनके पड़ोसी सचिन वर्मा ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 5 अगस्त की सुबह तालपुरा इलाके में हुई, जो नवाबाद थाने के अंतर्गत आता है। पुलिस के मुताबिक, भानु प्रकाश सरवरिया एक रिटायर्ड अडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसल (ADGC) थे और सूद पर पैसे उधार देने का काम भी करते थे। उनके पड़ोसी सचिन वर्मा के साथ उनका पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। सचिन ने सरवरिया से 60,000 रुपये उधार लिए थे और कर्ज न चुका पाने की वजह से वकील ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली थी। इसके अलावा, सचिन का मानना था कि सरवरिया ने उसके एक पुराने केस में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। साल 2001 में सचिन पर अपनी गर्लफ्रेंड के अपहरण और यौन शोषण का केस दर्ज हुआ था, जिसमें सरवरिया उसका वकील था। सचिन को लगता था कि वकील की लापरवाही की वजह से उसे सजा हुई। पिछले साल भी इस केस में कोर्ट ने सचिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके चलते उसे तीन महीने जेल में बिताने पड़े।

अंकम ने संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता

नई दिल्ली – सोलापुर के प्रसिद्ध हथकरघा कारीगर राजेंद्र सुदर्शन अंकम को हथकरघा क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए 'संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया।

1962 में सोलापुर में जन्मे राजेंद्र अंकम पिछले 48 वर्षों से एक पारंपरिक बुनकर के रूप में हथकरघा कला का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से बुनाई का कौशल प्राप्त करके और 100 बुनकरों को प्रशिक्षित करके इस कला को पुनर्जीवित किया है। उनके काम ने सोलापुर के हथकरघा उद्योग को एक नया आयाम दिया है और नई पीढ़ी को प्रेरित किया है।

स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 24 उत्कृष्ट कारीगरों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 6 महिलाएँ और 1 दिव्यांग कारीगर शामिल थे। उन्हें हथकरघा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया, सांसद कंगना रनौत, कपड़ा सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव (कपड़ा) रोहित कंसल, हथकरघा आयुक्त डॉ. एम. बीना और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार सृजन क्षेत्र है। उन्होंने डिज़ाइनरों और बुनकरों से एक साथ आकर युवाओं को आकर्षित करने वाले आधुनिक हथकरघा उत्पाद बनाने की अपील की। इस अवसर पर एक हथकरघा प्रदर्शनी, 'वस्त्र वेद' फैशन शो और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई की एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी अनावरण किया गया।

खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं – कोकाटे

मुंबई – खेल और युवा कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे ने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें और उसमें निरंतरता बनी रहे। सह्याद्रि अतिथिगृह में खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद खेल मंत्री श्री कोकाटे ने समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल दिग्गीकर, आयुक्त शीतल तेली-उगले, उप सचिव सुनील पंधारे, संयुक्त निदेशक सुधीर मोरे, उप निदेशक संजय सबनीस, उप निदेशक उदय जोशी, उप निदेशक माणिक पाटिल, स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग के अवर सचिव अशोक दमयावार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए। आधुनिक खेल सुविधाएँ, प्रशिक्षक और प्रतिस्पर्धा के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अधिक से अधिक प्रशिक्षक तैयार किए जाएँ ताकि गुणवत्तापूर्ण खिलाड़ी बढ़ें। प्रशिक्षकों के लिए नई योजनाएँ तैयार की जाएँ। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए समन्वय से कार्य किया जाए ताकि खिलाड़ियों के साथ अन्याय न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि युवाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में युवाओं से अधिक से अधिक सुझाव लिए जाएँ और उन पर सकारात्मक विचार किए जाएँ। प्रदेश में कुल 162 खेल परिसर पूर्ण हो चुके हैं, तथा 138 खेल परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि अन्य स्थानों पर अद्यतन सुविधाओं सहित खेल परिसरों को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन

नई दिल्ली – देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों से राखी बंधवाई। आधिकारिक एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने तस्वीरों और वीडियो को शेयर भी किया है। देशभर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच देश के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं ने भी आज राखी के त्योहार का उत्सव मनाया और राखी बंधवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के अलग-अलग स्कूलों के बच्चों संग राखी का त्योहार मनाया। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, जिसमें महामहिम स्कूल के बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाते दिख रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों और छात्रों के साथ रक्षा बंधन मनाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों संग राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया। पीएम मोदी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें पीएम मोदी बच्चों से राखी बंधवाते दिख रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'आज रक्षाबंधन के एक बेहद खास उत्सव की कुछ झलकियां यहां प्रस्तुत हैं। हमारी नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार।' इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने 7 अगस्त को कुछ तस्वीरों को शेयर किया था, जिसमें सीएम मोहन यादव महिलाओं से राखी बंधवाते दिख रहे हैं।

इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी यादव की बहनें उन्हें राखी बांधती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'भाई-बहन के अनूठे स्नेह, पवित्र प्रेम, अटूट संबंध सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता और भारतीय संस्कृति के विशिष्टता के प्रतीक #रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा परिवार और पार्टी से निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी शनिवार को रक्षाबंधन मनाया। तेज प्रताप यादव ने एक्स हैंडल पर कुछ फोटो शेयर कर बताया कि उन्हें राखी बांधने के लिए उनकी मौसी की बहन पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची। पूर्व मंत्री ने बताया कि शनिवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।

कोराडी मंदिर में अंडर कंस्ट्रक्शन गेट का स्लैब गिरा, 17 मजदूर घायल

नागपुर – कोराडी मंदिर में निर्माणाधीन गेट का स्लैब गिरने से 17 मजदूर घायल हो गए। हादसा शनिवार रात भारी बारिश के चलते हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर में स्थित कोराडी के महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थान में शनिवार रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी बारिश के चलते मंदिर के निर्माणाधीन गेट की स्लैब अचानक गिर जाने से 17 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों ने फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई।

जिला कलेक्टर विपिन इटंकर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निकेतन कदम खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील करते हुए कहा कि हादसे में 17 मजदूर घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया, 'स्लैब गिरने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है। विशेषज्ञ जल्द ही मौके का मुआयना करेंगे ताकि हादसे की वजह का खुलासा हो सके।' घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत पर डॉक्टर नजर रखे हुए हैं। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बचाव कार्य में सहयोग करें। मंदिर के निर्माणाधीन गेट का स्लैब गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल JCB की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते अलग-अलग इलाकों से दुर्घटना की खबरें भी सामने आई हैं। नागपुर में भी पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

संपादक की कलम से

कारागार पुस्तकालय में पहल

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा महाराष्ट्र में जेल पुस्तकालयों के लिए बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कैदियों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की साझा निधि योजना के अंतर्गत पुस्तकालय निदेशालय के राज्य के 60 कारागार पुस्तकालयों में से प्रत्येक को एक पुस्तक अलमारी और एक पुस्तक रैक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री निर्देश दिए थे ताकि कैदियों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित हो और उन्हें पढ़ने के अवसर मिलें, और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। राज्य की प्रत्येक जेल में बंद कैदियों को पढ़ने का अवसर प्रदान करने, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करने, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने तथा उनके सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के लिए पुस्तकालय निदेशालय के सहयोग से बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

मिलिंद दहिवले
संपादक

अंगदान सर्वोत्तम दान है...

अंगदान एक महादान है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। हालाँकि, समाज में अंगदान को लेकर कई भ्रांतियाँ और भय व्याप्त हैं, जिसके कारण अंगदान की दर बहुत कम है। इसी को दूर करने के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग ने 'अंगदान जीवन संजीवनी अभियान' नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। दुनिया का पहला मानव अंग प्रत्यारोपण 1954 में हुआ था, जबकि भारत में यह 1971 में सीएमसी वेल्लोर में हुआ था। दुर्भाग्य से, 75 साल बाद भी, भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। आज जितने भी अंग प्रत्यारोपण होते हैं, उनमें से ज़्यादातर सीधे तौर पर संबंधित दाताओं से होते हैं, जबकि ब्रेन-डेड मरीज़ों से प्राप्त मृत अंगदान हमेशा से ही पिछड़ा रहा है। इस नेक और मानवीय उद्देश्य के लिए, भारत में दस हज़ार में से केवल एक मरीज़ ही अंगदान के लिए सहमति देता है, जबकि पश्चिमी देशों में दस हज़ार में से लगभग 3500 लोग अंगदान के लिए सहमति देते हैं।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 18,900 है। मृतक दाताओं की संख्या 1,128 और जीवित दाताओं की संख्या 15,000 है। भारत में किडनी और लिवर प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल रोगियों की संख्या और अंगदान दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक प्रतिशत से भी कम है। 2024 के अंत तक, भारत को अंतिम चरण की किडनी और लिवर की बीमारियों के इलाज के लिए 2 लाख किडनी और 1 लाख लिवर की जरूरत होगी। हालाँकि, हर साल केवल 4,000 किडनी ट्रांसप्लांट और 500 लिवर ट्रांसप्लांट ही किए जाते हैं, जिससे हज़ारों मरीज़ नए जीवन के इंतज़ार में अंगों की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। हृदय की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ 5,000 मरीज़ों को हृदय की ज़रूरत है और केवल 253 हृदय प्रत्यारोपण ही किए जा सके हैं। 220 फेफड़े प्रत्यारोपण किए गए हैं।

वर्तमान में, भारत में लगभग 570 अंग प्रत्यारोपण केंद्र और केवल 140 गैर-प्रत्यारोपण अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र हैं, जो जनसंख्या की वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। दूसरी बात, इनमें से अधिकांश निजी संस्थान हैं, जहाँ इलाज का खर्च हर किसी के लिए वहन करने योग्य नहीं है। समाधान के रूप में, कम लागत वाले और किफायती प्रत्यारोपण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, जिनमें से कई इलाज के दौरान ब्रेन डेड हो जाते हैं। एक ब्रेन डेड मरीज़ 2 किडनी, 1 लिवर, 1 हृदय, 2 फेफड़े, 1 अग्न्याशय का संभावित दाता हो सकता है और एक साथ 7 लोगों की जान बचा सकता है। वह कॉर्निया, त्वचा, हड्डियों जैसे ऊतक भी दान कर सकता है और विकलांग मरीजों को विभिन्न विकलांगताओं से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। राज्य में अंगदान की दर बढ़ाने और अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों को नया जीवन देने के उद्देश्य से 3 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों के साथ अंगदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने पहल करते हुए आवेदन पत्र भरवाकर अंगदान का संकल्प लिया और इस अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने राज्यवासियों से इस अभियान में भाग लेने और अंगदान का संकल्प लेने की अपील की है।

अंगदान एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। इस विषय पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रभावी जन-जागरूकता आवश्यक है। अभियान के माध्यम से अंगदान से जुड़े भय, भ्रांतियों और अंधविश्वासों को दूर करना तथा लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है। इसके लिए, राज्य में 3 अगस्त से 15 अगस्त तक 'अंगदान, जीवनदान, संजीवनी अभियान' चलाया जा रहा है। इस दौरान व्यापक जन-जागरूकता एवं समुदायोन्मुखी गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज, गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक संस्थाएँ, स्वास्थ्य संस्थाएँ और समाजसेवी आदि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के अभियान का नारा है "देहदान, महादान, दूसरों को जीवनदान"। इस अभियान के तहत, आशा स्वयंसेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी गांवों, बस्तियों और बस्तियों में घर-घर जाकर अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, अंगदान के बारे में गलत धारणाओं पर प्रकाश डालेंगे, लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अंगदाताओं का सम्मान करेंगे और जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन देने के लिए प्रेरित करेंगे।

अंगदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने शरीर से किसी अंग को निकालकर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए कानूनी सहमति देता है। यह या तो दाता के जीवित रहते हुए सहमति से, मृत्यु से पहले मृतक द्वारा किए गए दान के लिए कानूनी अनुमति से, या मृतक के कानूनी निकटतम संबंधी की अनुमति से किया जाता है। यह दान अनुसंधान उद्देश्यों के लिए या, अधिक सामान्यतः, किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण हेतु स्वस्थ प्रत्यारोपण योग्य अंगों और ऊतकों का दान करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्यारोपण में गुर्दे, हृदय, यकृत, अग्न्याशय, आंतें, फेफड़े, हड्डियाँ, अस्थि मज्जा, त्वचा और कॉर्निया शामिल हैं। कुछ अंग और ऊतक जीवित दाताओं द्वारा दान किए जा सकते हैं, जैसे कि गुर्दा या यकृत का कोई भाग, अग्न्याशय का कोई भाग, फेफड़े का कोई भाग, या आंत का कोई भाग, लेकिन अधिकांश दान दाता की मृत्यु के बाद होते हैं।

अंगदान कई लोगों की जान बचा सकता है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई ज़रूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। अंगदान एक सामाजिक कार्य है। यह समाज की मदद करता है और ज़रूरतमंद लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मौका देता है। ऐसा माना जाता है कि अंगदान किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के शरीर में जीवन जीने का दूसरा मौका देता है। अंगदान उन लोगों को जीवन जीने का दूसरा मौका देता है जिनके अंग खराब हो गए हैं या जो गंभीर चिकित्सा स्थितियों से जूझ रहे हैं। अंगदान के बारे में भ्रांतियाँ: कुछ लोगों में अंगदान के बारे में धार्मिक भ्रांतियाँ हैं। हालाँकि, कई धर्म अंगदान का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि अंगदान से मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में देरी होती है। हालाँकि, अंगदान की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाती है। कुछ लोगों में चिकित्सीय भ्रांतियाँ हैं कि अंगदान से उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालाँकि, अंगदान करते समय डॉक्टर आवश्यक सावधानी बरतते हैं।

अंगदान करने के लिए आप राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) या अन्य मान्यता प्राप्त अंगदान संगठनों की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। अंगदान करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराना और उनकी सहमति लेना आवश्यक है।

शूटिंग के लिए नयनतारा मुंबई पहुंची

दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानीमानी अभिनेत्री नयनतारा फिल्म टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के अगले शेड्यूल के लिए मुंबई पहुंच गयी हैं। अखिल भारतीय फिल्म, टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स, सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने के लिए तैयार है। वर्तमान में फिल्मांकन चरण में, प्रोडक्शन अब अपने नवीनतम शूटिंग शेड्यूल के लिए मुंबई चला गया है। उत्साह को बढ़ाते हुए, अभिनेत्री नयनतारा भी मुंबई पहुंचकर शूटिंग में शामिल हो गईं।

नयनतारा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसमें वह अपनी विशिष्ट शान और सहज शैली में नजर आईं। टीम मुंबई, गोवा और बेंगलुरु सहित कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर फिल्मांकन कर रही है, जिससे रोमांच और तमाशा की दुनिया बन रही है। कुछ ही दिन पहले, रॉकिंग स्टार यश भी मुंबई पहुंचे।

टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स का निर्माण वेंकट के. नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत संयुक्त रूप से किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता गीतू मोहनदास कर रही हैं।19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह फिल्म एक्शन और ड्रामा का एक बेहतरीन रोलरकोस्टर होने का वादा करती है।

मृणाल ने अपने 'बचपन की यादें' साझा की

बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपने 'बचपन की यादें' साझा की है। मृणाल ठाकुर अक्सर अपने पिता के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे उनके रिश्ते की खूबसूरती दिखती है। मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की कुछ 'यादें' पोस्ट कीं। इसमें वह अपने पिता के साथ दिख रही हैं। मृणाल ठाकुर ने झूले पर बैठे हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके पापा पास खड़े दिखे। इस खूबसूरत पल को शेयर करते हुए मृणाल ने कैप्शन में लिखा, बचपन की यादें! लव यू पापा। उन्होंने वीडियो में आतिफ असलम का गाना 'मेरी कहानी' को भी साझा किया।

उर्वशी रौतेला ने मचाया धमाल

बहुप्रतीक्षित एक्शन से भरपूर फिल्म जाट का धमाकेदार डांस नंबर 'टच किया' रिलीज़ हो गया है। गाना 'टच किया' में ग्लैमरस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ खतरनाक विलेन जोड़ी रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह नजर आ रहे हैं। यह हाई-एनर्जी गाना , जिसे मधुबंती बागची और शाहिद मल्ल्या ने गाया है, कुमार ने लिखा है और थमन एस ने कंपोज किया है। गोपिचंद मालिनेनी निर्देशित फिल्म जाट में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसेंड्रा की भी अहम भूमिका है।

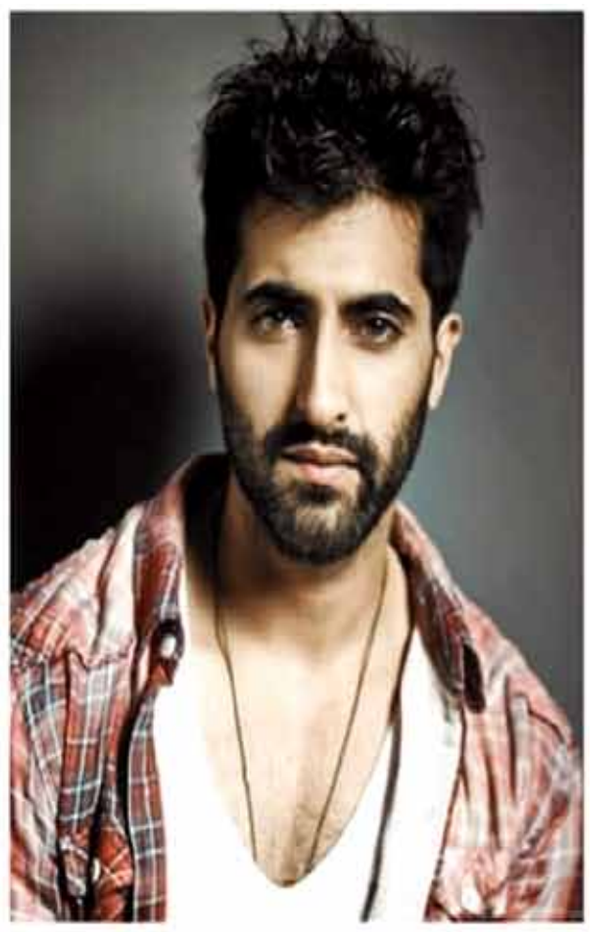

अक्षय ओबेरॉय सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेरॉय अपनी साउथ डेब्यू फिल्म टॉक्सिक के लिए कन्नड़ भाषा सीख रहे हैं। अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर अक्षय ओबेरॉय अब कन्नड़ फिल्म टॉक्सिक से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित एक्शन-थ्रिलर में वह सुपरस्टार यश के साथ नज़र आएंगे। अपने किरदार को पूरी तरह से वास्तविक और प्रभावी बनाने के लिए अक्षय इस समय कन्नड़ भाषा पर गहन प्रशिक्षण ले रहे हैं।

फिल्म के प्रोडक्शन टीम ने अक्षय के लिए भाषा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की है, जिससे वह न सिर्फ कन्नड़ उच्चारण को सही तरीके से सीख सकें, बल्कि अपने किरदार की भावनाओं को भी पूरी गहराई और सटीकता के साथ व्यक्त कर सकें। उनकी यह मेहनत न सिर्फ उनके अभिनय के प्रति समर्पण को दर्शाती है, बल्कि कन्नड़ सिनेमा के प्रति उनके सम्मान को भी दिखाती है।अपने इस नए सफर के बारे में अक्षय ने कहा, ₹नई इंडस्ट्री और भाषा में कदम रखना मेरे लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है।

मेरे लिए यह सिर्फ कन्नड़ संवाद याद करने का नहीं, बल्कि इस भाषा और संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर है, जिससे मैं अपने किरदार को वास्तविकता से निभा सकूं। प्रोडक्शन टीम ने मुझे बेहतरीन भाषा प्रशिक्षक दिए हैं, जो मेरे उच्चारण, शब्दों की ध्वनि और भावनाओं को संवारने में मदद कर रहे हैं। यश जैसे प्रेरणादायक सह-कलाकार के साथ काम करना भी एक शानदार अनुभव है। मैं इस फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं और कन्नड़ दर्शकों से एक गहरा जुड़ाव बनाना चाहता हूं।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी

NASA के 2 मिशनों पर ट्रंप की नजर, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता

वाशिंगटन – डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नजर नासा के अंतरिक्ष मिशनों पर भी लगी हुई है। ट्रंप प्रशासन नासा को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के दो मिशनों को बंद करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये मिशन ग्रीनहाउस गैस और पौधों की सेहत की निगरानी से जुड़े हैं। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा स्रोत बंद हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्ताव में 'ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी' मिशनों के लिए कोई धनराशि शामिल नहीं है। ये मिशन सटीक रूप से दिखा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां उत्सर्जित और अवशोषित हो रही है तथा फसलें कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। नासा ने ईमेल पर भेजे एक बयान में कहा कि इन्हें 'राष्ट्रपति के एजेंडे और बजट प्राथमिकताओं के अनुरूप' समाप्त किया जा रहा है। इस बीच, नासा के एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डेविड क्रिस्प ने कहा कि इन मिशनों में इस्तेमाल की गई तकनीक अब भी दुनिया की किसी भी मौजूदा या प्रस्तावित प्रणाली की तुलना में अधिक संवेदनशील और सटीक है। ये एक 'राष्ट्रीय संपत्ति' हैं जिन्हें बचाया जाना चाहिए। क्रिस्प के अनुसार, इन मिशनों की मदद से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि अमेजन वर्षावन जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, उससे अधिक उत्सर्जित करता है, जबकि कनाडा, रूस और उन क्षेत्रों (जहां बर्फ पिघल रही है) के बोरियल वन अधिक अवशोषण करते हैं। क्रिस्प ने कहा, "यह वाकई महत्वपूर्ण है। हम इस तेजी से बदलते ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं।" मिशिगन विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक जोनाथन ओवरपेक ने कहा कि मिशनों को समाप्त करने का निर्णय "बेहद अदूरदर्शितापूर्ण" है। उन्होंने कहा, "इन उपग्रहों द्वारा प्रदान किए गए अवलोकन, अमेरिका सहित पूरे ग्रह पर बढ़ते जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

उत्तरी एरिजोना में विमान हादसा प्लेन क्रैश में 4 की गई जान

अमेरिका – उत्तरी एरिजोना में एक चिकित्सा परिवहन विमान हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है। एक चिकित्सा परिवहन विमान उत्तरी एरिजोना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद विमान आग लग गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क स्थित सीएसआई एविएशन कंपनी का यह विमान फ्लैगस्टाफ से लगभग 200 मील (321 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में चिनले हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार लोग चिकित्साकर्मी थे जो एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहे थे। संघीय उड्डयन प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बीचक्राफ्ट 300 दोपहर में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और एफएए इसकी जांच कर रहे हैं। दुर्घटना का कारणों अब तक पता नहीं चल सका है। नवाजो जनजाति के अध्यक्ष बुउ न्यग्रेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुर्घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने कहा, 'ये वो लोग थे, जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया नुकसान को गहराई से महसूस किया जा रहा है।' जिला पुलिस कमांडर एम्मेट याजी ने कहा, "वो वहां उतरने की कोशिश कर रहे थे और दुर्भाग्य से कुछ गड़बड़ हो गई।" बता दें कि, इससे पहले इसी साल जनवरी में, फिलाडेल्फिया में एक चिकित्सा परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा था कि विमान का वॉयस रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था। हाल ही में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ओक आइलैंड के पास एक विमना समुद्र में क्रैश हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब लोग आइलैंड के किनारे सैर रहे थे। हादसा शनिवार, 2 अगस्त 2025 की शाम को हुआ था।

कनाडा में 51 फीट ऊंची प्रभु राम की प्रतिमा स्थापित

कनाडा – उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची प्रभु श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना हुई है। इसके साथ ही जयश्रीराम के जयकारों की गूंज से पूरा शहर ऊर्जावान हो रहा है। इसकी ऊंचाई आधार को छोड़कर 51फीट है। कनाडा में के मिसीसॉगा शहर में प्रभु श्रीराम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची राम प्रतिमा है। इससे हिंदू श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। मिसीसॉगा शहर में रविवार को हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। आधार से उसकी ऊंचाई 51 फीट से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है। इस प्रतिमा की स्थापना के साथ ही कनाडा जयश्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।

यह प्रतिमा ओंटारियो के हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित है। यह प्रतिमा उत्तर अमेरिका में हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का नया प्रतीक बन गई है। कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदायों के लिए श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना एक ऐतिहासिक क्षण रहा। इस प्रतिमा का अनावरण रविवार को ओंटारियो के मिसिसॉगा स्थित हिंदू हेरिटेज सेंटर में किया गया। यह प्रतिमा फाइबरग्लास से बनी हुई है। यह मूर्ति अब ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित हो गई है।

इस उद्घाटन समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिनके साथ कई प्रमुख राजनेता भी उपस्थित थे। इनमें महिलाएं और कनाडा की मंत्री रेची वल्डेज़, ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष शफकत अली, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू शामिल थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। कनाडा में प्रभु श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना के बाद लोगों ने मेक कनाडा ग्रेट अगेन का नारा दिया। वहीं एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "अयोध्या से ओंटारियो तक, श्रीराम का नाम सीमाओं से परे गूंज रहा है। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह आस्था और पहचान का ऐसा प्रतीक है जो पूरी दुनिया में ऊंचा खड़ा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, "टोरंटो, कनाडा: भगवान श्रीराम की सबसे ऊँची मूर्ति अब मिसिसॉगा में स्थापित हो चुकी है। यह वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। एक ऐसे देश में जहां हिंदुओं को कट्टर खालिस्तानी तत्वों से बढ़ती दुश्मनी का सामना करना पड़ा है, यह मूर्ति केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, शांति और अस्तित्व का प्रतीक है। सनातन धर्म ऊंचा खड़ा है। लोगों ने लिखा "चलो कनाडा को फिर से महान बनाते हैं। "भव्य और सुंदर!"

पडलसे सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल

मुंबई – अमलनेर तालुका (जलगाँव ज़िला) स्थित पडलसे (निचली तापी) सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। इस निर्णय से राज्य को 859.22 करोड़ रुपये मिलेंगे, यह जानकारी जल संसाधन (विदर्भ, तापी, कोंकण सिंचाई विकास महामंडल) एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने दी।

जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने पाडलसे (निम्न तापी) सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) (त्वरित सिंचाई लाभ योजना) में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा था। तदनुसार, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में निम्न तापी, चरण-1 परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस परियोजना के अंतिम चरण के लिए केंद्र सरकार से कुल 2,888.48 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 859.22 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की है। इस परियोजना को विभिन्न चरणों की मंजूरी की आवश्यकता थी। प्रारंभ में, परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए पीआईबी (सार्वजनिक निवेश बोर्ड) को भेजा गया था। तदनुसार, वित्त मंत्रालय से प्रारंभिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, संबंधित विभागों से उनकी टिप्पणियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) वुमलुनमंग वुलनम की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई और परियोजना को आगे की प्रक्रिया के लिए जल शक्ति मंत्रालय को भेज दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्रालय ने गहन जांच के बाद अंतिम मंजूरी दे दी और परियोजना को वापस जल शक्ति मंत्रालय को भेज दिया। अंत में, जल शक्ति मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) योजना में शामिल करने की घोषणा की है।

इस प्रक्रिया में, राज्य के जल संसाधन विभाग ने लगातार फ़ॉलो-अप किया और केंद्र सरकार को इस परियोजना के महत्व से अवगत कराया। केंद्र सरकार के इस फ़ैसले से कृषि के साथ-साथ उत्तर महाराष्ट्र के समग्र विकास को भी बल मिलेगा। इस परियोजना के लिए लगातार फ़ॉलो-अप जारी था। केंद्र सरकार के इस फ़ैसले ने परियोजना के पूरा होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें – कोकाटे

मुंबई – अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे ने उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने तथा उनका समग्र विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक एवं औकाफ विभाग का कार्यभार संभालने के बाद सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, जैन अल्पसंख्यक निगम के अध्यक्ष ललित गांधी, विभागीय सचिव रुचेश जयवंशी, आयुक्त प्रतिभा इंगले, उपसचिव मिलिंद शेनॉय और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अल्पसंख्यक विकास मंत्री कोकाटे ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थी स्कूली शिक्षा से वंचित न रहें और अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा तक पहुँचें, इसके लिए प्रयास आवश्यक हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर विभाग की विभिन्न पहलों की जानकारी दी गई। वर्तमान में, राज्य में लड़कियों के लिए 26 छात्रावास कार्यरत हैं और तीन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक नए छात्रावास को मंजूरी दी गई है। अल्पसंख्यक छात्रों की मराठी भाषा में दक्षता बढ़ाने के लिए मराठी फाउंडेशन कक्षाएं भी शुरू की गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और कोल्हापुर केंद्रों में 10 अनिवासी महिला अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जा रहा है। छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को भोजन भत्ता भी दिया जाता है। छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अमरावती संभाग के 15 जिलों में कुल 2,800 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएँगे और इन महिलाओं को कौशल विकास सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। बताया गया कि निवासी पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 50 उम्मीदवारों को एक निजी संस्था के माध्यम से तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य उर्दू अकादमी, राज्य हज समिति, राज्य वक्फ बोर्ड, जैन समुदाय अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अल्पसंख्यक विकास मंत्री कोकाटे ने योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

अंबरनाथ जैसे जीवंत और गतिशील शहर में एक नया न्यायालय भवन न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा

ठाणे – बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने आज यहां कहा कि अंबरनाथ जैसे जागरूक और गतिशील शहर में यह न्यायालय भवन न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब होगा। चिखलोली-अंबरनाथ में सिविल जज जूनियर लेवल और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय तथा नए न्यायालय भवन का उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने उपमुख्यमंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में किया। वे इस अवसर पर बोल रहे थे। न्यायमूर्ति श्री कुलकर्णी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अंबरनाथ जैसे स्थान पर इस न्यायालय

की स्थापना से न्याय मिलने में तेज़ी आएगी। चिखलोली-अंबरनाथ स्थित यह न्यायालय भवन आधुनिक है और यहाँ विभिन्न आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह आधुनिक भवन 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को साकार करने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा, "अंबरनाथ जैसे जागरूक और गतिशील शहर में, मुझे आशा है कि यह संरचना न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिम्ब बनेगी। इस उद्घाटन के अवसर पर, आइए हम न्यायालय को एक जीवंत संस्था के रूप में देखें, जो केवल कानून के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास के योग्य भी है।"

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आज जिस न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ है, वह अत्यंत सुंदर और विशाल है। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर की तरह, यह न्यायालय भी एक पहचान बनेगा। न्याय के इस मंदिर में सत्य की सदैव विजय होगी। राज्य में निष्पक्ष न्याय की परंपरा रही है। हम अनेक उद्घाटन करते हैं, लेकिन किसी न्यायालय का उद्घाटन करना आनंद और संतुष्टि का विषय है।" उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता को न्याय दिलाने वाली सरकार है। पिछले ढाई साल में 32 अदालतें स्थापित की गई हैं। सरकार न्याय व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम नागरिकों को अच्छे माहौल में न्याय मिलेगा। इसी तरह, सरकार न्याय व्यवस्था की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगी ताकि नागरिकों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे, न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना, ठाणे के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा के अध्यक्ष एडवोकेट विट्ठल कोंडे-देशमुख सहित वरिष्ठ वकील, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ वकीलों को सम्मानित किया गया तथा उल्हासनगर बार एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया गया।

भारत पर लगे 50 फीसदी टैरिफ के फैसले का ह्वाइट हाउस ने किया खुलासा

वाशिंगटन – अमेरिका ने भारत पर अचानक 50 फीसदी टैरिफ कैसे लगा दिया, आखिर ऐसे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर ही लगा दिया। ह्वाइट हाउस ने ट्रंप के इस फैसले का खुलासा किया है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और इसके बाद दोबारा 25 फीसदी टैक्स और लगा दिया। इस प्रकार भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया।यह दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका की ओर से लगाया गया सर्वाधिक टैरिफ है। भारत के बाद सिर्फ ब्राजील ऐसा दूसरा देश है, जिस पर ट्रंप ने 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। बाकी सभी देशों का टैरिफ भारत और ब्राजील के मुकाबले लगभग आधे के आसपास ही है। भारत पर इतना अधिक टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या बौखलाहट थी, इसका खुलासा खुद ह्वाइट हाउस ने किया है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। पीटर ने कहा कि भारत का यह इनकार अमेरिका के लिए ''राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा'' है। इसी वजह से पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50% हो गया।

अमेरिका के किसी दबाव के आगे भारत का नहीं झुकना और अपने जिगरी दोस्त रूस से तेल खरीदना जारी रखना ह्वाइट हाउस के लिए आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन गया। व्हाइट हाउस के अनुसार नवारो ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ''भारत पर लगाए गए शुल्क का तर्क पारस्परिक शुल्क से बिलकुल अलग है।'' उन्होंने कहा, ''यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, जो भारत के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा हुआ है और हर अमेरिकी को इसका गणित समझना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक स्थिति से संबंधित है।'' नवारो ने कहा, ''आप इस बात से समझिए कि भारत शुल्क का 'महाराजा' है, यह अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है और इसके पास ऊंची गैर-शुल्क बाधाएं भी हैं, जिससे हम अपने उत्पाद वहां नहीं पहुंचा पाते।

पीटर ने भारत पर आरोप लगाते कहा कि अमेरिका एक ''गैर न्यायसंगत व्यापारिक माहौल'' में भारत से उत्पाद ख़रीदने के लिए विदेशों में बहुत सारे डॉलर भेजता है। 'इसके बाद भारत इसी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करता है। फिर रूस भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अपने हथियारों के वित्तपोषण और यूक्रेनियों की हत्या के लिए करता है, और फिर अमेरिकी करदाताओं से उन हथियारों के लिए भुगतान करने को कहा जाता है जिनसे यूक्रेन को रूसी हथियारों से बचाना है और ये हथियार भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर से खरीदे जाते हैं।''

प्रधानमंत्री मोदी की शंघाई सहयोग संगठन में संभावित सहभागिता से गदगद हुआ चीन

बीजिंग – अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की संभावित बीजिंग यात्रा की खबर से चीन गदगद हो गया है। चीन ने पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम करार दिया है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की संभावित बीजिंग यात्रा की खबर से चीन गदगद हो गया है। चीन ने पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस महीने के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तियानजिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित यात्रा का शुक्रवार को स्वागत किया।

पीएम मोदी अगर चीन जाते हैं तो सात साल के अंतराल के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। बताया जा

रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। चीन ने कहा ''हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का एक संगम होगा। एससीओ अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवे। गुओ ने कहा कि एससीओ के सभी सदस्य देशों और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित 20 से अधिक देशों के नेता संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन एससीओ की स्थापना के बाद से सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी शिरकत कर सकते हैं।

न्यूज गैलरी

प्रशासनिक अधिकारी एवं पत्नी संघ के माध्यम से सिलाई मशीनों का वितरण

मुंबई – प्रशासनिक अधिकारियों और उनकी पत्नियों का संघ, आईएएसओडब्ल्यूए, सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध एक अखिल भारतीय गैर-लाभकारी संगठन है। इस संगठन की महाराष्ट्र शाखा के माध्यम से, एक स्वयं सहायता समूह की दो विधवा महिलाओं, शोभा अरुण नाइक और यास्मीन फिरोज मोमिन को सिलाई और कटर मशीनें वितरित की गईं। ये मशीनें आईडीबीआई के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत प्रदान की गई हैं। शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक समारोह में ये मशीनें वितरित की गईं। इस कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना मीणा, सचिव श्रीमती आर. विमला, कोषाध्यक्ष ज़ेबा नाइक, सुप्रिया चडगल, संस्था के पदाधिकारी और सदस्य, तथा आईडीबीआई के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बदमाश गिरफ्तार, 5 पिस्तौल और 51 कारतूस बरामद

मुंबई – मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 5 पिस्तौल और 51 जिंदा कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शूटरों के पास से 4 पिस्तौल और 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के पास से 5 अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जिन हथियारों को बरामद किया है, उसकी कीमत 87,900 रुपये बताई जा रही है।

पैसा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाकर राहत दी जाए - कदम

मुंबई – महाराष्ट्र वित्तीय संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी सक्षम प्राधिकारियों को जमाकर्ताओं की जमा राशि वसूल करनी चाहिए। इससे जमाकर्ताओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने निर्देश दिया है कि वे इसके लिए समर्पित भाव से काम करें। महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सक्षम अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई। यह पहली बार है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा ऐसी समीक्षा की गई। बैठक में मुंबई आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक दीपक देवराज, उप सचिव यमुना जाधव आदि उपस्थित थे। राज्य मंत्री श्री योगेश कदम ने कहा कि कानून के तहत जमाकर्ताओं का पैसा वसूलने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शीघ्रता से लागू की जानी चाहिए। सभी सक्षम प्राधिकारी नीलामी स्तर और न्यायालय स्तर पर उपलब्ध जानकारी, प्रकरणवार, अगले 15 दिनों के भीतर सरकार को प्रस्तुत करें। विभाग को इस संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अपराध की प्रकृति के आधार पर निपटाए जाने वाले मामलों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। साथ ही, मामलेवार समीक्षा की जानी चाहिए। इस पूरे कानून के क्रियान्वयन के लिए एक विशिष्ट कार्य प्रणाली तैयार की जानी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। सक्षम अधिकारियों को इस कानून की पूरी जानकारी हो, कानून पर कुछ सुझावों और संवाद का आदान-प्रदान हो, इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

स्तनपान को प्राथमिकता दें : मंडल रेलवे अस्पताल नागपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन

नागपुर – हर वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है ताकि शिशु और मातृ स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व को प्रोत्साहित किया जा सके। इस वैश्विक पहल के अंतर्गत 7 अगस्त 2025 को मंडल रेलवे अस्पताल, नागपुर में एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम "स्तनपान को प्राथमिकता दें: सतत समर्थन प्रणाली बनाएं" थी, जो इस बात पर बल देती है कि सफल स्तनपान के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और समुदायों से निरंतर सहयोग आवश्यक है। कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) डॉ. शुभांगी साखरे ने एक ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति दी, जिसमें स्तनपान के पोषणात्मक और भावनात्मक लाभों को विस्तार से बताया गया। उन्होंने समझाया कि जीवन के पहले छह महीनों के लिए स्तनपान अत्यंत आवश्यक है और यह मां और शिशु के बीच संबंध को मजबूत करता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मंगेश चौधरी ने बच्चों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर चर्चा की और बताया कि प्रारंभिक भावनात्मक जुड़ाव, विशेषकर स्तनपान के माध्यम से, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. निर्मला गुप्ता ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए "रूमिंग-इन" जैसी प्रथाओं को अपनाने और अस्पताल को शिशु–मैत्री वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे माताओं को स्तनपान में सहायता मिले। कार्यक्रम में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि स्तनपान केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों, परिवारों और समुदायों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। यह प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

धुले और नंदुरबार में रेलवे सुविधाओं के विकास के लिए रावल का रेल मंत्री को ज्ञापन

नई दिल्ली – विपणन, शाही प्रोटोकॉल मंत्री और धुले जिले के संरक्षक मंत्री, मंत्री जयकुमार रावल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और धुले और नंदुरबार जिलों में रेलवे सुविधाओं के विकास के संबंध में मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। बयान में दोंडाईचा स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव, दादर-भुसावल विशेष ट्रेनों का नियमितीकरण, भुसावल-पुणे नई रेल सेवा, प्लेटफार्म सुविधाओं का विकास, अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्यान्वयन और रेलवे कोचों का उन्नयन जैसी मांगें शामिल हैं। विपणन मंत्री रावल ने औद्योगिक, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में दोंडाईचा शहर के महत्व को रेखांकित करते हुए, दोंडाईचा स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की माँग की। नासिक और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राजमार्ग और निकटवर्ती तोरणमाल, बलसाणा तीर्थ स्थलों के कारण इस शहर का विशेष महत्व है। वर्तमान में, सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। साथ ही, रावल ने अनुरोध किया कि 2023 में शुरू होने वाली दादर-भुसावल विशेष ट्रेन (09051/52, 09049/50) को नियमित किया जाए, इसका किराया कम किया जाए और एलएचबी कोच का उपयोग किया जाए। दोंडाईचा स्टेशन पर ढके हुए प्लेटफ़ॉर्म की कमी के कारण सामान को नुकसान पहुँचता है और ट्रेन के रैक खाली होने का अनिश्चित समय विलंब शुल्क का कारण बनता है। यह भी अनुरोध किया गया कि एक ढका हुआ प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, सुबह 8 बजे से नौ घंटे की समय सीमा शुरू की जाए, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ और भुसावल-अमलनेर-शिंदखेड़ा-दोंडाईचा-पुणे जैसी एक नई सेवा प्रदान की जाए क्योंकि पश्चिम खानदेश से पुणे के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। रावल ने यह भी मांग की कि शिंदखेड़ा, दोंडाईचा और नरदाना स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए तथा कुछ ट्रेनों के प्रथम एसी और द्वितीय एसी के आधे डिब्बों को पूर्ण प्रथम एसी डिब्बों में अपग्रेड किया जाना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री श्री रावल ने विश्वास व्यक्त किया कि रेल मंत्री खानदेश में यात्रियों की सुविधा और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। इसके साथ ही, विपणन मंत्री श्री रावल ने केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन से सद्भावना भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

युवक के सिर में आर-पार हो गया 5 फीट लंबा सरिया

मुंबई – भिवंडी में 5 फीट लंबा सरिया युवक के सिर में घुसकर आर-पार हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। भिवंडी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भिवंडी में मेट्रो प्रोजेक्ट साइट के पास सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। नारपोली पुलिस स्टेशन के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के ब्रिज पर काम के दौरान एक 5 से 6 फीट लंबा लोहे का सरिया अचानक ऊपर से गिर गया। सरिया एक चलती रिक्शा पर गिरा और उसमें बैठे युवक के सिर में जा घुसा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सोनू शेख के रूप में हुई है, जो भंडारी कंपाउंड, विठ्ठल नगर का निवासी है और मज़दूरी करता है। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय वह बगे फिरदौस इलाके से खाना खाकर अपने घर लौट रहा था।

जैसे ही रिक्शा मेट्रो ब्रिज के नीचे से गुजरा, भारी लोहे का सरिया अचानक ऊपर से गिरा और सीधे युवक के सिर में जा घुसा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टरों को कटिंग मशीन से रॉड को काटना पड़ा, उसके बाद युवक को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। उसने बताया कि इससे पहले भी साइट से लोहे की रॉड गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस हादसे को एजेंसी की घोर लापरवाही का नतीजा बताया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर ये लापरवाही नहीं होती तो एक युवक को इतने बुरे हालात का सामना नहीं करना पड़ता।

जातिवादी पुलिस इंस्पेक्टर अशोक घोरबंद को बचाने की आखिरी कोशिशें नाकाम

नांदेड़ – परभणी में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान के अपमान के एक मामले से शहर में अफरा-तफरी मच गई और पथराव हुआ। पुलिस को शक था कि मौजूद भीड़ बेकाबू हो जाएगी, इसलिए उसने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस ने गलियों में घुसकर आंबेडकर अनुयायियों की पिटाई की, बल्कि लोगों के वाहनों और घरों के प्रवेश द्वारों पर भी लाठियों से तोड़फोड़ की। इसका वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुणे में पढ़ाई कर रहे सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के एक लड़के को, जो परभणी में कानून की परीक्षा देने आया था, पुलिस ने घेरकर पीटा। इस पिटाई में उसकी मौत हो गई। इस मामले में आंबेडकर अनुयायियों और सोमनाथ सूर्यवंशी की माँ ने कानून के ज़रिए न्याय की माँग की और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने अदालत में उनका पक्ष रखने की पहल की और इस मामले में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की। पीठ ने कहा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की पिटाई से मौत हो गई और उसे पीटने वाले लगभग 70 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिनमें प्रमुख परभणी पुलिस बल की स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अशोक घोरबंद थे। जब अशोक घोरबंद नांदेड़ में थे, तब भी उन पर बोंधर मामले में ऊंची जाति की मदद करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन वह इस मामले से बचने में सफल रहे। जब वह नांदेड़ में थे, तब उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में काम करने वाले दो शिकायतकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अशोक घोरबंद के खिलाफ भूख हड़ताल की और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। लेकिन यहां भी वह प्रशासन को संभालने में सफल रहे और परभणी में स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख के रूप में काम करते हुए, अदालत ने दर्ज किया कि

सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या उनके द्वारा की गई थी। नांदेड़ के ऊंची जाति के विधायक इस जातिवादी को बचाने की कोशिश कर रहे थे इस बार अशोक घोरबंद यह कहने में सफल रहे कि वे अपराधी नहीं हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च सदन, विधान परिषद में विधायक हेमंत पाटिल ने परभणी मामले का उदाहरण दिया और इस मामले को न्याय के कटघरे में लाया गया। इसके बावजूद, उन्होंने जातिवादी पुलिस निरीक्षक अशोक घोरबंद को यह सवाल करके बचाने की कोशिश की कि पुलिस कैसे निर्दोष है या वे उसे उस काम के लिए दोषी मानते हैं जो उसे करना चाहिए था, जब उसे करना चाहिए था। इसके बाद, मुंबई उच्च न्यायालय की संभाजीनगर पीठ ने इस मामले में अशोक घोरबंद सहित 70 पुलिसकर्मियों को आरोपी घोषित किया और मामला दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन परभणी पुलिस ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आज, उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद परभणी पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया और इस पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस वजह से, जातिवादी अशोक घोरबंद को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों के प्रयास विफल माने गए हैं और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सबकी नजर इस बात पर है कि नांदेड़ परभणी हिंगोली जिले के पुलिस उपमहानिरीक्षक शाहजी इस मामले को लेकर परभणी पुलिस को क्या निर्देश देते हैं।

नागपुर में रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ

नागपुर – 'आत्मनिर्भर भारत' का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण। जागरूकता और प्रशिक्षण से आदिवासी महिलाएं सर्वांगीण प्रगति कर सकेंगी और इन महिलाओं के लिए कला के साथ-साथ कौशल भी अर्जित करना आवश्यक है। साथ ही, यदि ज्ञान को प्राथमिकता दी जाए और ज्ञान को कौशल में और कौशल को धन में परिवर्तित किया जाए, तो आदिवासी महिलाएं सशक्त और मजबूत बनेंगी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा।

गडकरी आदिवासी विकास विभाग द्वारा कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आयोजित रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, आदिवासी विकास राज्य मंत्री डॉ. अशोक उइके, राज्य मंत्री एडवोकेट. इस अवसर पर आशीष जायसवाल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, श्याम कुमार बर्वे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक कृपाल तुमाने, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त श्रीमती लीना बंसोड़, अपर आयुक्त श्रीमती आयुषी सिंह, पूर्व महापौर माया इवनाते, गोंड राजे वीरेंद्र शाह, मानकर ट्रस्ट के अध्यक्ष शिरोलकर आदि उपस्थित थे। गडकरी ने उपस्थित महिलाओं को विस्तृत मार्गदर्शन देते हुए कहा कि केंद्र

और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को उद्योग में अवसर प्रदान कर रही हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आदिवासी विकास विभाग राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करे, तो उन्हें रोजगार मिलना संभव है। श्री गडकरी ने आदिवासी महिलाओं से रानी दुर्गावती के आदर्श को अपने सामने रखने की भी अपील की।

डॉ. उइके ने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय की महिलाओं के अंतर्निहित कौशल और कलात्मक गुणों को बढ़ावा दिया जाए, तो आदिवासी समुदाय विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार आदिवासी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना मुख्य रूप से उन आदिवासी महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है जो अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का सपना देखती हैं और रोजगार सृजन में अपनी पहचान बना सकें। केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी महिलाओं के विकास में पूर्ण सहयोग दे रही हैं और इस समाज के हर वर्ग के लिए उन्नति की योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। छात्राओं को छात्रवृत्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ की योजनाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन सभी उपजातियों को विकास की धारा में लाने के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

डॉ. उइके ने बताया कि आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को पूरे मन से सहेजने के लिए जाना जाता है और हम जल, ज़मीन और जंगल के प्रति उनकी भावनाओं को जानते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं की कला और छुपे गुणों को बढ़ावा देने और उनके हस्तशिल्प को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर सकारात्मक विचार किए जा रहे हैं। आदिवासी महिलाएँ चित्रकला, कपड़ों पर चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने और आभूषण बनाने में अग्रणी हैं। उन्होंने आदिवासी महिलाओं से पहल करने की अपील की ताकि कला की यह विरासत निरन्तर बढ़ती रहे और यह कला समय के साथ लुप्त न हो।

देश का विकास सामाजिक एकता पर निर्भर करता है। श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को शामिल करने वाली योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। रानी दुर्गावती ने उस काल में वीरांगनाओं की एक सेना तैयार की थी। इसे महिलाओं के सशक्त होने का एक बड़ा प्रमाण बताते हुए, श्री उइके ने विश्वास व्यक्त किया कि ये महिलाएँ सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, कर्मयोगी योजना आदि योजनाओं से आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण को और बल मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएँ एनीमिया, सिकलसेल और कुपोषण से पीड़ित हैं और उन्होंने इन महिलाओं से इनके समाधान के लिए किए जा रहे उपायों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कृषि और वन उत्पादों के लिए बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध करा रही है, जिससे इन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर उभरी है। श्री जायसवाल ने कहा कि बुनियादी ढाँचे के निर्माण से भले ही भौतिक जीवन में बदलाव आया हो, लेकिन राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार वन क्षेत्रों में आदिवासियों के सामूहिक विकास और विकास के लक्ष्य को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक धनराशि खर्च की जा रही है और वन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और श्याम कुमार बर्वे ने उपस्थित जनसमूह को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित आदिवासी महिलाओं को साहित्य वितरित किया गया। यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आदिवासी महिलाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों को नागरिकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का परिचय श्रीमती लीला बंसोड़ ने दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएँ उपस्थित थीं।